Developing a Culture of Sustainable Consumption and Lifestyle through Organic Production and Consumption in the State of Rajasthan (ProOrganic II) 2017-2021

CUTS International

Supported by:

Swedish Society for Nature Conservation

Background

India is mainly an agricultural country where around 58 percent of nation's population is dependent on agriculture for livelihood. There is huge untapped potential for organic farming in the country. Organic farming emerged as a potential alternative for meeting increasing food demand, maintaining soil fertility and increasing soil carbon pool.

The promotion of sustainable consumption and production is directly related to consumer's safety and demand for organic products can be created in many ways. This is an important aspect of sustainable development, which depends on achieving long-term economic growth that is in accordance with environmental and social needs. Use of pesticides and chemicals in agriculture production is one of the major causes of environmental degradation and is quite harmful for human health. The chemicals in food products adversely affect reproduction capabilities in women and girls. Moreover, Indian societies being largely patriarchal needs of women are not prioritised. Hence, they are likely to suffer from chemical contamination of food. Therefore, adoption of organic consumption will benefit mostly the female population of India.

ProOrganic II: An Overview

'ProOrganic' project was initiated in November, 2013 to promote organic consumption in the State of Rajasthan. The objective of the project was to create demand among consumers for organic products and sensitise farmers for shifting towards organic farming and advocacy on issues related to organic farming. The project was concluded in March, 2017 with major activities getting accomplished in a span of three years like Awareness Generation Campaigns, Organic Fairs, Farmer's Training and Exposure Visits, Consultations apart from research components in the project area. The project had a deep impact as a remarkable increase in the area of organic farming was observed in the State. In addition, there was also a hike in demand for organic products by the consumers.

Looking at the success of phase-I, the Swedish Society for Nature Conservation (SSNC) further agreed to extend its support for another four years to implement phase-II of the project entitled 'Developing a Culture of Sustainable Consumption and Lifestyle through Organic Production and Consumption in the State of Rajasthan (ProOrganic II)' from April 01, 2017 to March 31, 2021 in 192 gram panchayats (in 10 selected districts of Rajasthan, India).

One of the basic idea of the project is promoting sustainable consumption and production, which are important aspects of sustainable regime. This is largely consistent with the environmental and social factors, and education and empowerment of consumers. In 'ProOrganic II' project, focus is on the aspect of sustainable food and farming, and to formulate an agenda to achieve it. This will be acquired through promoting organic production of farm products on one hand, and promoting organic consumption, on the other. Consequently, this would lead to sustainable development in agriculture and environmental sector, as a whole. The target group of the project comprises entire population of the covered 10 districts, 96 blocks and selected 192 gram panchayats in Rajasthan.

Project Objectives

- To develop a culture of sustainable development through sensitisation awareness generation, and education on organic consumption and production
- To generate awareness among consumers about organic products like benefits, availability etc.
- To build capacity of farmers to adopt organic farming
- To promote and increase consumer's demand for organic products
- To encourage consumers to shift towards organic products and sustainable consumption and
- To sensitise and advocate with the concerned stakeholders including government agencies to promote organic products in Rajasthan prone

Project Activities

The proposed activities of the project will be as given below:

- Scoping Visits
- Project Launch and Partner's Orientation Meeting
- Base Line Survey
- Awareness Campaign on Sustainable Consumption
- Training and Exposure Visit of Farmers
- Farmer's Trainings (One Training Exclusively for Women Group)
- Green Action Week
- Follow up Workshop on Human Rights Based Approach (HRBA)
- Establishment of Organic Compost Cell
- Establishment of Community Seed Bank
- Formation of Organic Clubs and Developing Organic Gardens in Schools
- Organic Fairs
- State Level Sensitisation Workshops with Media
- State Level Stakeholder's Consultation Meeting
- End Line Survey to Gauge Project Effectiveness
- Publishing Relevant Information, Education and Communication (IEC) Materials

Project Duration: The duration of the phase-II of the Project will be from April 01, 2017 to March 31, 2021

Project Districts: Two gram panchayats from each block of ten districts – Jaipur, Dausa, Udaipur, Chittaurgarh, Pratapgarh, Kota, Jodhpur, Jhalawar, Bhilwara and Sawai Madhopur will be covered under the project (192 gram panchayats of 96 Blocks in 10 selected districts).

"This document has been produced with the financial contribution by the Swedish International Development Co-operation Agency (SIDA) through the Swedish Society for Nature Conservation, (SSNC). The views herein shall not necessarily be taken to reflect the official opinion of SSNC or its donors."

CUTS CART
CUTS Centre for Consumer Action, Research & Training
D-218 A, Bhaskar Marg, Bani Park, Jaipur 302016, India, Phone: 91.141.2282821
Fax: 91.141.2282485, 4015395; E-mail: cart@cuts.org; Web: www.cuts-international.org/CART

राजस्थान राज्य में जैविक उत्पादन व उपभोग द्वारा सतत् उपभोग व जीवनशैली की संस्कृति का विकास (प्रोऑर्गेनिक II) 2017-2021

CUTS International

सहयोग:

Swedish Society for Nature Conservation

पृष्ठभूमि

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहॉ देश की 58 प्रतिशत आबादी की आजीविका का मुख्य स्त्रोत कृषि है। भारत में जैविक खेती के लिए बहुत संभावनाएं हैं। जैविक खेती मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने एवं सतत् उपभोग खाद्य की मांग को बनाए रखने के लिए एक विकल्प के रूप में उभरी है।

जैविक उत्पादन व उपभोग के द्वारा सतत् उपभोग को बढ़ावा देने का सीधा संबंध उपभोक्ता सुरक्षा एवं जैविक पदार्थों के लिए मांग बढ़ाने से भी जुड़ा हुआ है। जैविक उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा देना, सतत् विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है एवं पर्यावरण और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप है। खेती में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग पर्यावरण प्रदूषण एवं मानव स्वास्थ्य खराब होने का मुख्य कारण है। खाद्य पदार्थों में रासायनिक पदार्थ महिलाओं में संतान उत्पत्ति की क्षमता को प्रभावित करते हैं। वैसे भी भारतीय समाज मुख्य रूप से पुरूष प्रधान होने से महिलाओं की प्राथमिकताओं पर कम ध्यान दिया जाता है। इसलिए वे खाद्य पदार्थों में रासायनिक संदूषण से ज्यादा प्रभावित होती हैं। इसलिए जैविक उपभोग निश्चित तौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए लाभदायक रहेगा।

प्रोओर्गेनिक (द्वितीय) परियोजना के बारे में

राजस्थान राज्य में जैविक उपभोग को बढ़ावा देने के लिए नवम्बर, 2013 में प्रोजेक्ट 'प्रोओर्गेनिक' शुरू किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं में जैविक पदार्थों के प्रति मांग बढ़ाना, किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करना तथा इससे सम्बन्धित स्थानीय मुद्दों पर पैरवी करना था। इस परियोजना के तहत चार साल के समय में विभिन्न गतिविधियां जैसे, जागरूकता कार्यशालाएं, जैविक मेले, किसानों का प्रशिक्षण एवं भ्रमण, पैरवी बैठके आदि हिस्सा थे। इस परियोजना ने राज्य मे जैविक खेती के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी तथा उपभोक्ताओं की तरफ से जैविक पदार्थों की मांग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला।

परियोजना के पहले चरण की सफलता को देखते हुए एस.एस.एन.सी. (स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कन्जरवेशन) ने इस परियोजना के दूसरे चरण के लिए सहयोग की सहमति दी, जो कि चार वर्ष की है तथा परियोजना का शीर्षक 'राजस्थान राज्य में जैविक उत्पादन व उपभोग द्वारा सतत् उपभोग व जीवनशैली की संस्कृति का विकास (प्रोओर्गेनिक II)' है। जो कि अप्रेल 01, 2017 से राजस्थान के 10 जिलों की 192 ग्राम पंचायतों में आरम्भ जाएगी।

इस परियोजना की मूल अवधारणा यह है कि सतत् उपभोग एवं उत्पादन को बढ़ावा देते हुए सतत् जीवन शैली के विकास को एक मुख्य पहलू बनाना जो कि पर्यावरणीय एवं सामाजिक कारकों तथा उपभोक्ताओं की शिक्षा एवं अधिकारिता से प्रत्यक्ष संबंध रखता है। इस परियोजना में जैविक खाद्य और खेती के पहलू पर ध्यान केन्द्रित करते हुए इसे एक तरफ कृषि उत्पादों के जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने तथा दूसरी तरफ जैविक उपभोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक कार्यसूची तैयार करना, जिसके फलस्वरूप कृषि में सतत् विकास हो। इस परियोजना का लक्ष्य चयनित 10 जिलों की 96 पंचायत समितियों की 192 ग्राम पंचायतों की जनसंख्या पर ध्यान केन्द्रित करना है।

परियोजना के उद्देश्य

- जैविक उपभोग और उत्पादन पर संवेदनशील जागरूकता उत्पन्न करना और शिक्षा के माध्यम से सतत् विकास की संस्कृति विकसित करना।
- जैविक उत्पादों के बारे में उपभोक्ताओं के मध्य जागरूता पैदा करना (लाभ, उपलब्धता इत्यादि)।
- किसानों की जैविक खेती को अपनाने के लिए क्षमतावर्धन करना।
- जैविक उत्पादों के लिए उपभोक्ताओं की मांग को बढ़ावा देने का प्रयास करना।
- उपभोक्ताओं को जैविक उत्पादों और सतत् उपभोग के लिए प्रोत्साहित करना।
- राजस्थान राज्य में जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी संस्थाओं सहित सम्बन्धित अन्य संस्थाओं को संवेदनशील बनाना और इस हेतु पैरवी करना।

परियोजना की गतिविधियां

परियोजना की प्रस्तावित गतिविधियां का आयोजन निम्नानुसार होगा;

- क्षेत्रीय भ्रमण
- परियोजना का शुभारम्भ एवं परियोजना सहभागियों के लिए आमुखीकरण बैठक
- क्षेत्र की वस्तुस्थिति के अध्ययन हेतु आधारभूत शोध
- सतत् उपभोग पर जागरूकता अभियान
- किसानों का प्रशिक्षण और भ्रमण
- किसानों का प्रशिक्षण (विशेषकर महिला समूह के लिए एक प्रशिक्षण)
- ग्रीन एक्शन वीक
- मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण (एच.आर.बी.ए.) पर कार्यशाला
- ओर्गेनिक कम्पोस्ट सेल की स्थापना
- सामुदायिक बीज बैंक की स्थापना
- स्कूलों में जैविक क्लबों का गठन और जैविक उद्यान का विकास करना
- जैविक मेले
- मीडिया के साथ राज्य स्तर की पैरवी बैठक
- सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं के साथ राज्य स्तर की पैरवी बैठक
- परियोजना की प्रभावशीलता मापने के लिए अंत रेखा सर्वेक्षण
- सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) सामग्री का प्रकाशन

परियोजना अवधिः चारवर्षीय परियोजना की अवधि अप्रेल 01, 2017 से मार्च 31, 2021 तक है।

परियोजना जिलेः दस जिलों के प्रत्येक ब्लॉक से दो ग्राम पंचायतों का चयन करना। जयपुर, दौसा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा, जोधपुर, झालावाड़, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर को इस परियोजना के तहत शामिल किया जाएगा। (दस चयनित जिलों में 96 ब्लॉक की 192 ग्राम पंचायतें समाहित होंगी)।

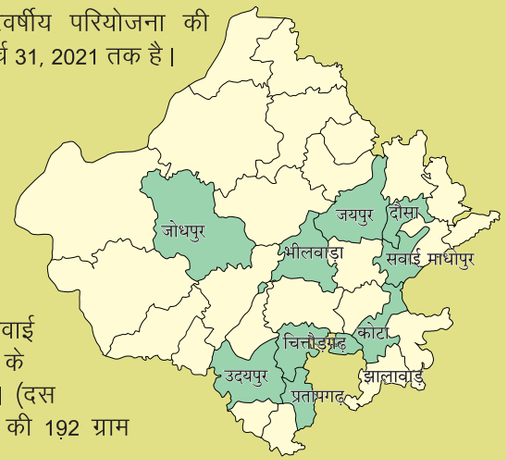

कट्स कार्ट

कट्स सेंटर फॉर कन्ज्यूमर एक्शन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग
डी–218 A, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, भारत, फोनः 91.141.2282821
फैक्सः 91.141.2282485, 4015395; ई–मेलः cart@cuts.org; वेबसाईटः www.cuts-international.org/CART